PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

(PM - KISAN) Current Status and Way Forward

PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI (PM –KISAN)

Salient Features

- **Central Sector income support scheme - to supplement financial needs of land holding farmers launched on 24th February'19.**
- **Direct Benefit of Rs. 6,000 per year, in three, 4-monthly installments of Rs 2,000 each, per farmer family.**
- **Originally for landholding SMFs - extended to all landholding farmers - Cabinet decision dated 31.5.2019**
- **Payments to be made after Aadhar authentication of records for beneficiaries due from Dec'19 (Aadhar authentication started since Aug'19, however, as per the cabinet approval dated 9.10.2019 extended till 31st Nov'19)**
- **The Scheme is being implemented online through Direct Benefit Transfer (DBT) mode for which an exclusive web-portal www.pmkisan.gov.in has been created.**

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM - KISAN)

योजना के बारे में :-

- पी एम किसान योजना एक सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे किसानो को आय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 24 फरवरी 2019 को लांच किया गया था।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर चार महीने में ,तीन समान किश्तों में, रु 6000 प्रतिवर्ष ,सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है।
- आरम्भ में यह योजना केवल सीमान्त कृषकों (२ हेक्टेयर से काम जोत वाले) के लिए थी, बाद में 31.5.2019 के कैबिनेट निर्णय के उपरांत यह सभी किसानों के लिए लागु हो गयी।
- दिसंबर 2019 के बाद का भुगतान लाभार्थियों के आधार रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है। (आधार प्रमाणीकरण, अगस्त से शुरू हुआ था, बाद में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार इस तिथि को दिसंबर तक विस्तारित किया गया था)
- योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जा रहा है, जिसके लिए एक विशेष वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in बनाया गया है।

Exclusions from PM KISAN

- **All Institutional Land holders**
- **Farmers' families who are Non-resident Indians (NRIs) in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961**
- **Farmer families with member(s) belonging to following categories -**

CONSTITUTIONAL POSITION HOLDERS

- Former and present holders of constitutional posts

MPs, MLAs etc.

- Former & present Ministers
- Former/present Members of LS/ RS/ State Legislative Assemblies/Councils
- Former & present Mayors of Municipal Corporations or Chairpersons of District Panchayats

SERVING/ RETIRED GOVERNMENT OFFICIALS

- Employees of Central/ State Government Ministries, Departments and its field units
- Central or State PSEs and Autonomous Institutions under Government
- Regular employees of the Local Bodies

WORKING PROFESSIONALS

- Doctors
- Engineers
- Lawyers
- Chartered Accountants, and Architects etc. registered with Professional bodies
- Persons who paid Income Tax in last assessment year

PENSIONERS

- Superannuated/retired pensioners with monthly pension >=Rs.10,000/ *(Excluding MTS/Group-IV/Group D Employees)*

पीएम-किसान का पात्र न होने की शर्तें/ गैर-पात्रता मापदंड

- सभी संस्थागत भू-धारक,
- क़िसान परिवार, जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की श्रेणी में हैं
- वे किसान परिवार जिनमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हो:-

संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति	सांसद, विधायक आदि	सेवारत/सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी	पेशेवर	पेंशन-भोगी
• पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति	• पूर्व और वर्तमान मंत्री • लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य • नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर या जिला पंचायतों के अध्यक्ष	• केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालय, विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के कर्मचारी, • सरकार के अधीन केंद्रीय या राज्य की सार्वजानिक क्षेत्र की इकाइयों, स्वायत्त संस्थानों स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी	• डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट्स आदि पेशेवर • अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति	• सेवानिवृत पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10000 रुपये से अधिक है (एमटीएस / ग्रुप- IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)

Alternative Implementation Mechanisms for some states

For NE States with community landholding – alternate mechanism for eligibility of farmers has been devised.

Manipur:

- **Certificate Issued by Village authority, namely the Chairman/Chief authorizing tribal family to cultivate a piece of land (duly authenticated by concerned sub-divisional officers) shall be accepted.**

Nagaland:

- **(i) In case of community owned cultivable land in the state of Nagaland which is under permanent cultivation, the certificate issued by the village council/authority/village chieftain, verified by the administrative head of the circle/ sub division and countersigned by the Deputy Commissioner of the District.**

कुछ राज्यों में योजना को लागु करने की विशेष व्यवस्था

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि के स्वामित्व अधिकार समुदाय आधारित होते हैं। ऐसे राज्यों मे किसानों के लिए पात्रता से संबंधित वैकल्पिक कार्यान्वयन कार्यतंत्र को विकसित किया गया है

- मणिपुर के मामले में ग्राम प्राधिकारी नामत: अध्यक्ष/मुखिया, भूमि पर काश्तकारी करने के लिए प्राधिकृत जनजातीय परिवार द्‍वारा जारी प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जा सकता है।
- नागालैंड : (i) नागालैंड राज्य में सामुदायिक स्वामित्व वाली खेती योग्य भूमि के मामले में, जो कि स्थायी खेती के अधीन है, भूमि धारण के संबंध में ग्राम परिषद / प्राधिकरण / गांव के मुखीया द्‍वारा जारी प्रमाण पत्र, विधिवत सत्यापित सर्कल / सब डिवीजन के प्रशासनिक प्रमुख और जिले के उपायुक्त द्‍वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए परिचालन दिशानिर्देशों के तहत पात्र हैं जो कुछ अपवर्जनों के अध्यधीन है.

Alternative Implementation Mechanisms for some states (cont..)

Nagaland:

- (ii) In case of cultivable land in the State of Nagaland which is categorized as Jhum land, the identification of beneficiaries shall be on the basis of certification of land holding by the village council / chief / head of the village, duly verified by the administrative head of the circle/sub division and countersigned by the Deputy Commissioner of the District.
- Provided that the name of the beneficiary is included in the state of Nagaland’s Agriculture Census of 2015-16.
- This proviso shall not be applicable in cases of succession and family partition.

Jharkhand

- The farmer will be asked to submit 'Vanshavali'(Lineage) linked to the entry of land record comprising his/her ancestor's name.
- After approval of the Gram Sabha, the village level/ Circle level revenue-officials will verify and authenticate the Vanshawali and possession of holding.
- This list shall be countersigned by the District level Revenue authority.

कुछ राज्यों में योजना को लागु करने की विशेष व्यवस्था (जारी...)

नागालैंड

- नागालैंड राज्य में खेती योग्य भूमि के मामले में, जिसे नागालैंड में झूम भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके प्रमाणन का आधार पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा भू-जोतो के स्वामित्व से है जो कि सर्कल / सब डिवीजन के प्रशासनिक प्रमुख /जिले के उपायुक्त द्वारा सत्यापित और इसके द्वारा गिना जाएगा।
- बशर्ते कि लाभार्थी का नाम नागालैंड की 2015-16 की कृषि संगणना में शामिल हो।
- यह अनंतिम उत्तराधिकार और परिवार विभाजन के मामलों में लागू नहीं होगा। ऐसे लाभार्थियों की सूची परिचालन दिशानिर्देशों के तहत बहिष्करण के अधीन होगी।

झारखंड

- किसान को भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी 'वंशावली' (वंश) और उत्तराधिकार का चार्ट जमा करने के लिए कहा जाएगा जिसमे उसके अथवा उसके पूर्वज का नाम शामिल होगा।
- ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद, ग्राम स्तर / सर्कल स्तर के राजस्व-अधिकारी, वंशावली और भूमि जोतों के कब्जे को प्रमाणित करेंगे।
- यह सूची जिला स्तरीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित की जाएगी।

Alternative Implementation Mechanisms for some states (cont..)

- **Forest dwelling tribes:** Tribal Holding 'Pattas' under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act,2006 shall be eligible for receiving the benefits under the PM KISAN scheme, subject to other eligibility conditions.

कुछ राज्यों में योजना को लागु करने की विशेष व्यवस्था (जारी...)

- **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006:** सरकार ने उन जन-जातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिन्हें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पट्टे दिए गए हैं। बशर्ते कि उन पर पात्रता से संबंधित अन्य शर्तें लागू होंगी।

Process Flow of PM-KISAN

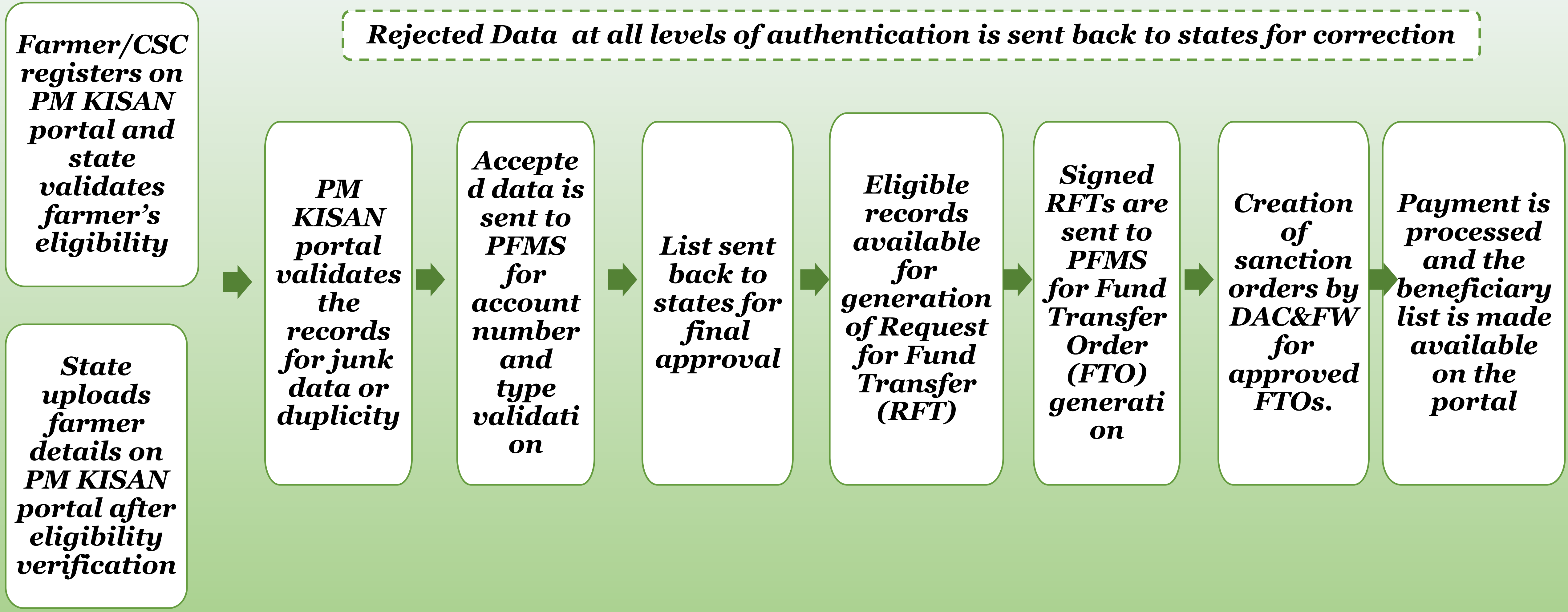

सम्मान राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया

किसान CSC या पी एम किसान पोर्टल पर रजिस्टर करता है और राज्य किसान की पात्रता की जांच करता है

राज्य पात्रता सत्यापन के बाद पीएम किसान पोर्टल पर किसान का विवरण अपलोड करता है

प्रक्रिया के दौरान हर स्तर पर गलत पाये गए डाटा को सुधार के लिये राज्य के पास भेज दिया जाता है

→ पीएम किसान पोर्टल राज्य द्वारा अपलोड किये गए विवरण से गलत या अमान्य डाटा को अलग करता है

→ पी एम किसान पोर्टल द्वारा स्वीकृत डाटा को अकाउंट संबन्धी सत्यापन के लिए पी एफ एम एस के पास भेजा जाता है

→ पी एफ एम एस द्वारा सत्यापन के बाद किसानों की सूची को अंतिम सहमति की लिए पुनः राज्य के पास भेजा जाता है

→ अंतिम रूप से स्वीकृत किसानों की सूची के आधार पर राज्य RFT (फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट) निर्गत करता है

→ निर्गत RFT के आधार पर पी एफ एम एस FTO (फंड ट्रांसफर आर्डर) निर्गत करता है

→ स्वीकृत FTO के आधार पर विभाग द्वारा सेंक्शन आर्डर जारी किया जाता है .

→ सम्मान राशि किसानों के खाते में जमा कर दी जाती है, एवं किसानों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाती है

State-wise Saturation Data

State Name	Estimated Landholdings	Saturation %
PUNJAB	10,43,429	227.69
MANIPUR	1,40,084	179.70
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	11,232	150.64
ASSAM	25,49,913	145.41
NAGALAND	1,92,283	132.02
MIZORAM	83,584	120.55
HARYANA	15,22,833	110.66
UTTAR PRADESH	2,25,73,509	103.24
GUJARAT	51,55,643	101.31
HIMACHAL PRADESH	9,46,038	97.02
UTTARAKHAND	8,09,613	94.20
JAMMU AND KASHMIR	13,30,169	85.75
ODISHA	46,84,277	84.73
RAJASTHAN	76,05,792	83.54
DELHI	18,393	78.56
DADRA AND NAGAR HAVELI	14,206	74.63
CHANDIGARH	638	72.39
JHARKHAND	25,56,434	71.75

State Name	Estimated Landholdings	Saturation %
MAHARASHTRA	1,39,87,297	68.96
MADHYA PRADESH	1,00,08,342	68.54
CHHATTISGARH	38,40,178	67.20
ANDHRA PRADESH	83,92,462	65.65
TELANGANA	58,56,015	62.26
ARUNACHAL PRADESH	1,06,761	61.41
KARNATAKA	84,18,625	60.81
TAMIL NADU	73,19,773	51.25
DAMAN AND DIU	7,707	47.76
KERALA	72,70,095	41.42
BIHAR	1,58,20,816	37.75
TRIPURA	5,35,813	37.62
MEGHALAYA	2,25,421	37.35
PUDUCHERRY	32,200	34.61
SIKKIM	61,390	26.90
GOA	55,228	21.86
LAKSHADWEEP	9,746	17.43
WEST BENGAL	68,14,061	0.00
GRAND TOTAL	**14,00,00,000**	**70.30**

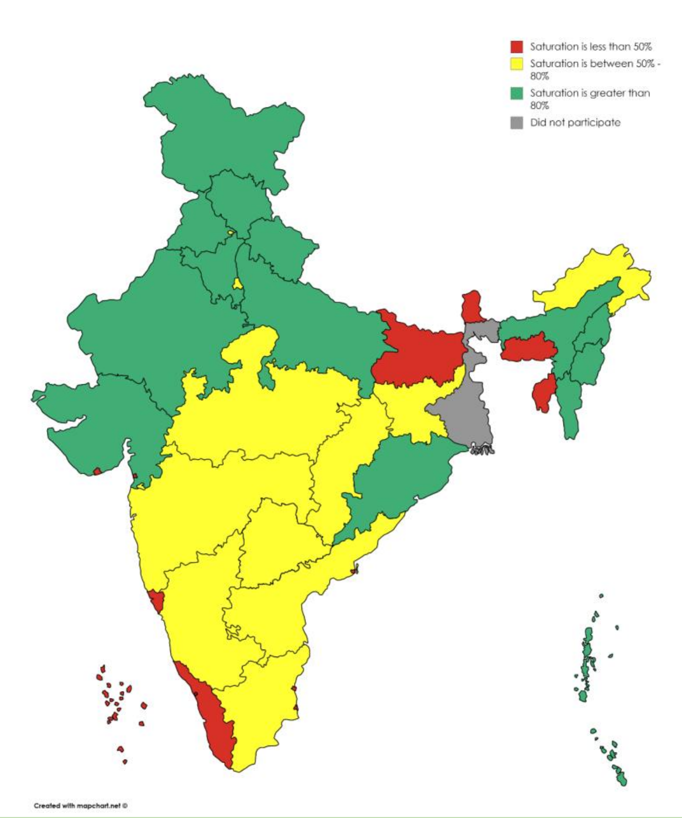

Saturation is >= 80%

Saturation is between 50% - 80%

Saturation is < 50%

Did not participate

State-wise Data for Online Registration

S.No	State Name	Total Farmer Registered (A + B)	Total Farmer Registered by Self (A)	Total Farmer Registered by CSC (B)
1	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	9	6	3
2	ANDHRA PRADESH	22,848	16,739	6,109
3	ARUNACHAL PRADESH	123	40	83
4	ASSAM	39,543	16,827	22,716
5	BIHAR	24,303	18,687	5,616
6	CHANDIGARH	121	78	43
7	CHHATTISGARH	1,61,518	1,11,969	49,549
8	DADRA AND NAGAR HAVELI	21	12	9
9	DAMAN AND DIU	11	6	5
10	DELHI	633	410	223
11	GOA	30	28	2
12	GUJARAT	81,942	48,094	33,848
13	HARYANA	3,38,512	1,42,863	1,95,649
14	HIMACHAL PRADESH	4,902	3,244	1,658
15	JAMMU AND KASHMIR	13,004	4,248	8,756
16	JHARKHAND	2,02,161	1,18,953	83,208
17	KARNATAKA	24,054	12,626	11,428
18	KERALA	40,647	27,406	13,241

State-wise Data for Online Registration

S.No	State Name	Total Farmer Registered (A + B)	Total Farmer Registered by Self (A)	Total Farmer Registered by CSC (B)
19	LAKSHADWEEP	1	0	1
20	MADHYA PRADESH	6,75,594	4,40,730	2,34,864
21	MAHARASHTRA	12,94,325	5,09,806	7,84,519
22	MANIPUR	1,53,755	55,835	97,920
23	MEGHALAYA	723	295	428
24	MIZORAM	3,841	2,741	1,100
25	NAGALAND	14,950	5,860	9,090
26	ODISHA	1,75,251	83,876	91,375
27	PUDUCHERRY	43	36	7
28	PUNJAB	12,36,209	8,96,935	3,39,274
29	RAJASTHAN	91,231	73,608	17,623
30	SIKKIM	11	9	2
31	TAMIL NADU	2,07,809	1,59,726	48,083
32	TELANGANA	1,01,863	31,355	70,508
33	TRIPURA	1,010	346	664
34	UTTAR PRADESH	17,00,068	12,11,150	4,88,918
35	UTTARAKHAND	36,231	11,347	24,884
36	WEST BENGAL	10,88,622	5,13,905	5,74,717
Grand Total :		**77,35,919**	**45,19,796**	**32,16,123**

Issues and Strategy to Achieve Saturation

- **West Bengal has not joined the scheme. Beneficiary potential of 68 lakh. Farmers are applying directly on the portal now. This issue needs to be addressed.**
- **Bihar potential is 158 lakhs whereas data of only 59.7 lakh uploaded. State has adopted a beneficiary application based approach which is delaying identification and upload.**
- **States which have achieved 90% or more saturation have been asked to look at inter district variations. States to do 100% verification of 25 randomly selected villages in comparatively low saturation districts.**
- **States which are claiming saturation at less than 80% of potential, have been asked to do physical verification of 25 villages in their comparatively high saturation districts as well.**
- **Cross district variation of saturation level across the state indicates untapped beneficiary coverage.**

योजना-कवरेज बढ़ाने के लिए किये गए प्रयास और चुनौतियाँ

- पश्चिम बंगाल योजना में शामिल नहीं हुआ है, लाभार्थियों की संख्या लगभग 68 लाख। किसान अब सीधे पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं।
- बिहार में लाभार्थियों की संख्या लगभग 158 लाख है जबकि केवल 59.7 लाख का डेटा अपलोड किया गया है। राज्य ने लाभार्थी आवेदन की एक अलग पद्धति अपनायी है जिससे पहचान और अपलोड करने में देरी हो रही है ।
- जिन राज्यों में 90% या अधिक आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं ,उन्हें अंतर-जिला विषमताओं की जांच के लिए कहा गया है। राज्यों को तुलनात्मक रूप से कम प्रतिशत पंजीकरण वाले जिलों में 25 गांवों का 100% प्रत्यक्ष सत्यापन करना है।
- वह प्रदेश जो 80 % से कम प्रतिशत पंजीकरण पर ही पूर्ण पंजीकरण का दावा कर रहे हैं, उन्हें अधिक पंजीकरण वाले जिलों के २५ गावों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है.
- किसी राज्य में लाभार्थियों के जिलेवार पंजीकरण -प्रतिशत में गहन विषमता इस बात का सूचक है उस राज्य में अभी सभी लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं हुआ है

Revised estimate of Target - group

At 9.84 Cr enrollments, pace of new beneficiaries registration has plateaued. However, many States including Bihar and West Bengal still have Approximately 2.13 Cr potential beneficiaries left to be included in the scheme.

Though 11.97 crore is statistically derived figure, empirical evidence suggests that saturation level will reach around 10 crore farmer families

1.31Cr + **0.82 Cr** = **2.13 Cr**

Approx. no. of potential beneficiaries left to be added by **Bihar & West Bengal**	Approx. no. of potential beneficiaries left to be added by other states	Total beneficiaries left to be added
1.31Cr	0.82 Cr	2.13 Cr

Agri-Census Estimate 14 Cr

Revised Estimate 11.97 Cr

Current Level of Registrations 9.84 Cr

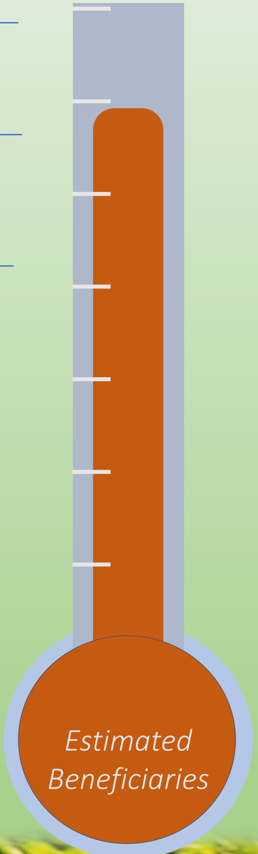

पात्र किसान परिवारों की संख्या का पुनरीक्षित अनुमान

- 9.84 करोड़ नामांकन के बाद ,नए लाभार्थियों के पंजीकरण की गति में गिरावट आई है। हालांकि, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में अभी भी लगभग 2.13 करोड़ संभावित लाभार्थी हैं जिन्हें योजना में शामिल किया जाना बाकी है।

- यद्यपि 11.97 करोड़ का अनुमान सांख्यिकीय गणना पर आधारित है, लेकिन नए पंजीकरणों की धीमी गति के आधार पर कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों तक पहुँचने का अनुमान है।

1.31Cr + **0.82 Cr** = **2.13 Cr**

1.31Cr	0.82 Cr	2.13 Cr
बिहार और पश्चिम बंगाल में शेष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या	अन्य राज्यों में शेष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या	कुल शेष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या

कृषि जनगणना के आधार पर अनुमान 14 Cr

सांख्यिकीय आधार पर पुनरीक्षित अनुमान 11.97 Cr

लाभार्थियों के पंजीकरण की वर्तमान संख्या 9.84 Cr

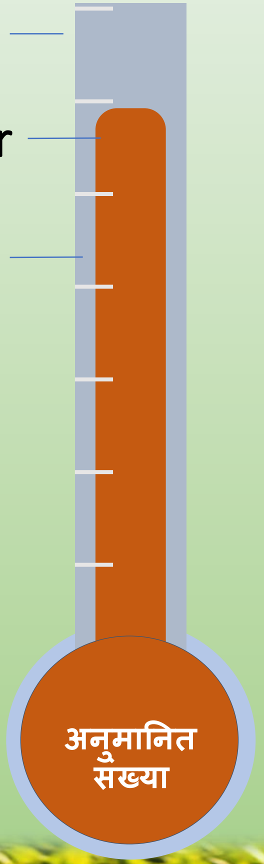

Current Status of Benefit Transfer

As on 20-Feb-2020

	No. of beneficiaries	Total Payment (in INR Crore)
Number of farmers paid for the 1st period – 1-Dec-2018 to 31-Mar-2019	4,33,58,732	8,672
Number of farmers paid for the 2nd period – 1-Apr-2019 to 31-Jul-2019	6,93,82,057	13,876
Number of farmers paid for the 3rd period – 1-Aug-2019 to 30-Nov-2019	7,65,48,863	15,310
Number of farmers paid for the 4th period – 1-Dec-2019 to 31-Mar-2020 *(This is an ongoing period)*	6,42,88,726	12,858
Total (in INR Crores)		50,716

New Farmers Added – Period Wise

	No. of Unique Beneficiaries
Number of new farmers added for the 1st period – 1-Dec-2018 to 31-Mar-2019	4,33,58,732
Number of new farmers added for the 2nd period – 1-Apr-2019 to 31-Jul-2019	2,75,24,638
Number of new farmers added for the 3rd period – 1-Aug-2019 to 30-Nov-2019	99,30,830
Number of new farmers added for the 4th period – 1-Dec-2019 to 31-Mar-2020 *(This is an ongoing period)*	37,22,128
Total	8,45,36,328

New Initiatives

- Farmers' Corner added to portal with following facilities
  - Self Registration by farmer
  - Aadhaar correction
  - Beneficiary Status
- Common Service Centers across the country enabled to provide direct services to farmers for Registration, Correction of records and Status verification
- Data Analytics on PFMS invalidated data being done at central level to remove discrepancies
- 24x7 IVRS based help line launched for status verification. Farmers can dial 1800-11-5526 or 155261 to know the status of their application.
- Data of more than 84% of the registered beneficiaries is Aadhaar verified
- PM KISAN Mobile App to be launched for direct services to beneficiaries
- "National Farmers Welfare Program Implementation Society" society has been formed to further the implementation of the scheme.

योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए नयी पहलें

- पी एम किसान पोर्टल पर खोले गए किसान कॉर्नर पर उपलब्ध सुविधाएँ
  - स्वतः पंजीकरण
  - आधार सम्बन्धी डाटा में सुधार
  - लाभार्थी के आवेदन की स्थिति की जानकारी
- स्वतः पंजीकरण,आधार सम्बन्धी डाटा में सुधार और लाभार्थी के आवेदन की स्थिति की जानकारी की सुविधा अब निकटस्थ जन सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध है
- पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट किये गए डेटा की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास केंद्रीय स्तर पर डाटा एनालिटिक्स के द्वारा किया जा रहा है
- किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा 24 x7 आईवीआरएस आधारित हेल्प-लाइन स्थापित की गयी है। किसान बंधु 1800115526 अथवा 155261 पर डायल कर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- लगभग 84 % आवेदकों के डाटा को आधार -लिंक्ड किया जा चुका है।
- शीघ्र ही पी एम किसान पोर्टल का मोबाइल एप्प भी विकसित किये जाने की योजना है
- "राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी" इस योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित की गयी है।

Thank You
धन्यवाद !!!!